

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1 देहरादून दिनांक 20 सितम्बर, 2007

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष की अनुसूचित जाति उप योजना (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1953/ नियो/जि०यो०/एस०सी०पी०/ 2007-08 दिनांक 24.8.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की अनुसूचित जाति उपयोजना (जिला सेक्टर) में कुल रूपया 24.73 लाख रुपये (रु० चौबीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) समाज कल्याण नियोजन प्रकल्प द्वारा तैयार की गयी वेबसाइट <http://gov. ua.nic.in/socialwelfarempr> पर अनुसूचित जाति उपयोजना की मासिक प्रगति, योजनावार लाभान्वित लाभार्थियों की सूची तथा सामूहिक लाभ वाले कार्यक्रमों की सूची जनपदवार उपलब्ध कराये।
- (2) राज्य गठन के उपरान्त वर्षवार माह मार्च की अनुसूचित जाति उपयोजना की प्रगति एवं योजनावार लाभान्वित लाभार्थियों की सूची/सामूहिक योजनाओं का वर्षवार /जनपदवार पूर्व विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित प्रारूप पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।
- (4) सभी कार्यक्रमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण तत्काल किया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की रूचना उपलब्ध करा दी जाय।
- (5) उक्त धनराशि केवल अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित सहकारी समितियों के उत्थान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत जिला योजना में स्वीकृत परिव्यय के अनुसार व्यय किया जाय तथा ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी इसके

लिये समुचित रूप से जिम्मेदार होगा और उनसे अनाधिकृत व्यय भी वसूली की जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह के अन्त में या अगले माह की 5 तारीख तक बी०एम०-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/ शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करे।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/गद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में भित्तव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय भित्तव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय वितरण सहित शासन/ महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

2. प्रश्नगत मद में गत वित्तीय वर्ष में निर्गत स्वीकृति के सम्प्रेष किये गये कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिनों के अन्दर शासन एवं महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

3. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या -30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता -आयोजनागत-107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 800-अन्य व्यय एवं 6425-सहकारिता के लिये कर्ज -आयोजनागत -107-जमा सहकारी समितियों को कर्ज के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक /योजनाओं के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०संख्या-205(P)/वित्त अनुभाग-4 /2007 दिनांक 12.9.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोपरि।

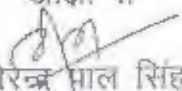
भवदीय
(डा०रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या:- 333 (1)/XIV-1/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओवरराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।।
- 2-समस्त कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

- 3-निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।
- 4- गित्ता अनुभाग-4 / रामाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शारंग।
- 5-निदेशक, एन0आई0सी0, राबिनालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(वीरन्द्र माल सिंह)
अनुसंधिव।

[illegible]

(वीर-२३/पाल सिंह)

अ. नं. १३३